

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *272
05.01.2018 को उत्तर के लिए
वन अध्ययन और अनुसंधान संस्थान

*272. श्री भरत सिंह:

श्री मानशंकर निनामा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में वन संबंधी अध्ययन और अनुसंधान तथा वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक विनिर्दिष्ट संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) देश में बढ़ रही जनसंख्या के कारण घट रहे वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'वन अध्ययन और अनुसंधान संस्थान' के बारे में दिनांक 05.01.2018 को उत्तर के लिए श्री भरत सिंह और श्री मानशंकर निनामा द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *272 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

- (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का देश में वन संबंधी अध्ययन एवं अनुसंधान तथा वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक विनिर्दिष्ट संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का देहरादून स्थित स्वायत्त संगठन- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित अपने नौ अनुसंधान संस्थानों तथा चार क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से समग्र अनुसंधान कर रहा है।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का देहरादून स्थित अधीनस्थ संगठन - भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन क्षेत्र का द्विवर्षीय आकलन करता है। इस आकलन के निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। इन रिपोर्टों की श्रृंखला में अद्यतन रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2015 है। इस रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश का कुल वन क्षेत्र 7,01,673 वर्ग कि.मी. है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.34% है। अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2013 की तुलना में देश में कुल वन क्षेत्र में 3775 वर्ग कि.मी. की निवल वृद्धि हुई है। देश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। कार्यान्वित की जा रही बड़ी स्कीमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

*वर्षवार वास्तविक लक्ष्य (हे.)		
2017-18	2018-19	2019-20
4180.8	4599.6	5059.2

*वास्तविक लक्ष्य वर्तमान वर्ष के बजट आवंटन के आधार पर और प्रतिवर्ष 10% वृद्धि किए जाने के दृष्टिकोण प्रस्तावित किए गए हैं।

राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, जो एक बड़ी वनीकरण/वृक्षारोपण स्कीम है। इस स्कीम को जनता की भागीदारी से देश में वनीकरण तथा अवक्रमित वन क्षेत्रों की पारि-बहाली के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है और इसके कार्यान्वयन में तीन स्तर अर्थात् ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियां, वन संभाग स्तर पर वन विकास एजेंसियां तथा राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसियां शामिल हैं। यह स्कीम मांग आधारित है और इसके तहत वनीकरण क्षेत्र की स्वीकृति, पिछले निष्पादन, पारि-बहाली के लिए उपलब्ध संभावित अवक्रमित वन भूमि तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है। वर्ष 2000-2002 में इस स्कीम की शुरुआत से अब तक 21 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके लिए वर्ष 2016-17 तक 3698.63 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 (30.10.2017 तक) के दौरान 58.46 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और 29067 हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया गया है।
